भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3862

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

बिहार में शैक्षणिक योजनाएं/परियोजनाएं

3862. **श्री दिनेश चंद्र यादव:**

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में जिला-वार कौन-कौन सी शैक्षणिक परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का बिहार में और अधिक उच्च शिक्षा परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है इसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के तहत, विभिन्न घटकों के अंतर्गत 8178.71 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 615 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2013 में रूसा की शुरुआत के बाद से पीएम-उषा के तहत 25 इकाइयों सहित 100 इकाइयों को बिहार में मंजूरी दी गई है, जिसमें योजना के विभिन्न घटकों के तहत 439.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। बिहार में स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार विवरण वेबसाइट https://pmusha.education.gov.in/pm-usha/assets/docs/Bihar%20-%20district-wise%20projects%20approved.pdf पर उपलब्ध है। राज्य को अब तक 137.10 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है, जिसमें विगत पांच वर्षों और जारी वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान जारी 76.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।

*****